



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1249]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 2008/चाद्र 11, 1930

No. 1249]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2008/BHADRA 11, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2008

सं. 36 (आरई-2008)/2004-2009

कार.आ. 2149(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009, (समय-समय पर यथासंशोधित) के पैरा 1.3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा विदेश व्यापार नीति में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. “व्यापार से संबंधित मामलों के लिए कानूनी खर्च को पूरा करने” के संबंध में पैराग्राफ 3.2.1.1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है :—

“वाणिज्य विभाग व्यापार से संबंधित मामलों के लिए कानूनी खर्च को पूरा करने के लिए निर्यात संबंधित परिषदों की सिफारिश सुपात्र नियंत्रकों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। तथापि, वित्तीय सहायता वाणिज्य विभाग की बाजार पहुँच पहल (एम.ए.आई.) स्कीम के तहत यथा उपलब्ध एजीकरण प्रभाव, एंटी डॉपिंग और काउन्टरवैलिंग मामलों में मुक्तमेवाजी जैसे कानूनी अनुपालन तक सीमित होगी।”

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/91/180/553/एम 09/पीसी-3]

आर. एस. गुजराल, विदेश व्यापार महाप्रदेशक

एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2008

No. 36 (RE-2008)/2004—2009

S.O. 2149(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with Para 1.3 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009 (as amended from time to time), the Central Government hereby makes the following amendment in Foreign Trade Policy :—

1. The Paragraph 3.2.1.1 regarding ‘Meeting Legal Expenses for Trade Related Matters’ is replaced as under :—

“DOC would provide financial assistance to deserving exporters on recommendation of EPCs for meeting cost of legal expenses for trade related matters. However, financial assistance would be restricted to statutory compliances such as registration charges, litigation in anti-dumping and countervailing cases, etc. as provided under the Market Access Initiative (MAI) Scheme of DOC.”

This issues in Public Interest.

[F. No. 01/91/180/553/AM 09/PC-3]

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade & ex-officio Addl. Secy.